पेज थ्री देहरादून
हमारा दून

सावन के पहले सोमवार पर टपकेश्वर मंदिर में जल चढ़ाते श्रद्धालु।

डेरी विकास में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारम्भ

शुभारम्भ

■मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में विभिन्न विभागों की योजनाएं की गई हैं शामिल

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत समेकित सहकारी विकास परियोजना व गंगा गाय महिला डेरी योजना में दुधारू पशु क्रय कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जहां मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसी योजना प्रारम्भ की गई है। इसमें कोविड–19 से प्रभावित होकर वापिस लौटे प्रवासियों के साथ ही युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उद्योग विभाग के तहत योजना प्रारम्भ करने के साथ ही अन्य विभिन्न विभागों की योजनाओं को भी इसमें समावेशित किया गया है। मुख्यमंत्री ने दूधली में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत समेकित सहकारी विकास परियोजना व गंगा गाय महिला डेरी योजना में दुधारू पशु क्रय कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

स्वरोजगार से ही आत्मनिर्भर भारत सम्भवः मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए स्वरोजगार की राह पर चलना होगा। हमने प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की है। इसमें ऋण व अनुदान की व्यवस्था की गई है। लगभग 150 प्रकार के काम इसमें लिए गए हैं। लाभार्थी अपनी रूचि और अनुभव के आधार पर इनमें से कोई भी काम शुरू कर सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रूपए का पैकेज दिया है। इसमें देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। राज्य में भी इसी क्रम में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का न केवल प्रारूप बनाया गया बल्कि इसका धरातल पर क्रियान्वयन भी शुरू किया जा चुका है। जिला योजना में स्वरोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

बद्री गाय के संरक्षण व दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य राज्य में दूध की उपलब्धता को बढ़ाना भी है। इसीलिए निर्णय लिया गया कि योजना के तहत दुधारू पशु राज्य के बाहर से लाए जाएंगे। साथ ही बद्री गाय के संरक्षण पर काम किया जा रहा है। बद्री गाय के घी की बाजार कीमत काफी अधिक है। कोशिश की जा रही है कि इनकी दुग्ध क्षमता को बढ़ाया जा सके। इसमें कुछ सफलता भी मिली है।

20 हजार दुधारू पशु का लक्ष्य

सहकारिता एवं दुग्ध विकास मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है, जहां मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरूआत हुई है। कोरोना की महामारी के बाद उत्तराखण्ड वासियों के लिए मुख्यमंत्री जी ने यह बड़ी सौगात दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के लाखों लोगों को रोजगार दिया जायेगा। डेरी विकास विभाग में राष्ट्रीय सहकारी विकास परियोजना के अंतर्गत डेरी क्षेत्र के लिए कुल 444.62 करोड़ रूपए स्वीकृत हैं। इसके तहत राज्य के दुग्ध सहकारी संघों के सुदृढ़ीकरण, कोल्ड चौन की स्थापना के साथ ही तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराने और प्रोत्साहन के लिए ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था की गई है। योजना के अंतर्गत लगभग 5400 लाभार्थियों को 20 हजार दुधारू पशु राज्य के बाहर से क्रय कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना के पहले वर्ष चालू वित वर्ष में लगभग 2800 लाभार्थियों को 10 हजार दुधारू पशु क्रय कराए जाएंगे। योजना के तहत इकाई लागत का 65 प्रतिशत ऋण, 10 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान और एनसीडीसी व राज्य अंतर्गत संचालित गंगा गाय महिला डेरी योजना से कुल 25 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। दुधारू पशुओं का बीमा पशुधन बीमा योजना में किया जाएगा। पूरे प्रदेश में 500 मिल्क बूथ की स्थापना की जा रही है। डेरी के क्षेत्र में स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार का प्रयास है कि इस क्षेत्र में प्रदेश के 10 हजार से अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके।

जल जीवन मिशन में मात्र एक रूपए में कनेक्शन

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना में हर घर को नल से जल की आपूर्ति की जाएगी। सरकार की कोशिश है कि लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले। वर्तमान में पेयजल कनेक्शन की कीमत 2350 रूपए है। परंतु इतनी राशि हर ग्रामीण द्वारा दिया जाना सम्भव नहीं है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत मात्र एक रूपए में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना से लम्बी लड़ाई है। हालांकि हम बेहतर स्थिति में आ गए हैं फिर भी तमाम सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। घर में बड़े बुजुर्गों और छोटे बच्चों का ध्यान रखें, मास्क की अनिवार्यता और फिजीकल डिस्टेंसिंग का पालन करें।

घर लौटे प्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड़–19 की स्थितियों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में प्रवासी भाईयों को उनके घर पहुंचाया गया है। उनके स्वास्थ्य, भोजन आदि की व्यवस्था की गई। इसके साथ ही इनमें से जो लोग अब उत्तराखण्ड में रहकर ही काम करना चाहते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में व्यवस्था की गई है। मनरेगा में 36 हजार नए रजिस्ट्रेशन करते हुए काम उपलब्ध कराया गया है।

महंगाई के विरोध में गरजे कांग्रेसी

मांग

■केन्द्र से इस बढ़ोत्तरी को वापस लिये जाने की मांग

देहरादून। **संवाददाता**

पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में बढ़ोत्तरी और बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेसजनों `ने राजधानी व आसपास के क्षेत्रों में स्थित पेट्रोल पम्पों पर केन्द्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और केन्द्र सरकार से इस बढ़ोत्तरी को वापस लिये जाने की मांग की गई।

राजधानी व आसपास स्थित पेट्रोल पम्प पर कांग्रेस कार्यकर्ता इकटठा हुए और वहां पर पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में बढ़ोत्तरी और बढ़ती महंगाई के विरोध में पेट्रोल पम्पों पर केन्द्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और केन्द्र सरकार से इस बढ़ोत्तरी को वापस लिये जाने की मांग की गई। इस अवसर पर राजपुर रोड़ स्थित यूनिवर्सल पेट्रोल पम्प पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष व विधायक प्रीतम सिंह कांग्रेसजनों के साथ वहां पर पहुंचे और केन्द्र के खिलाफ प्रदर्शन कर जनता को पत्रक भी बांटे।

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा अब समय आ गया है कि प्रदेश के लोगो को सामने आकर जनविरोधी कार्यो में लगी भाजपा को सबक सिखाना होगा। उन्होंने कहा कि आज डीजल के दाम बढ़ जाने से महंगाई आसमान छू रही है लेकिन सरकार सो रहीं है हमको इनको जगाने के लिए हमको इस तरह के कार्यक्रम करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज महंगाई चरम पर है और केन्द्र व राज्य सरकार इसे नियंत्रित नहीं कर पा रही है। आज डीजल के दाम पेट्रोल से ऊपर है और यह एक सोचनीय विषय है। उन्होंने कहा कि केन्द्र व राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष को तेज किया जायेगा।

पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि आज केन्द्र व राज्य सरकार में बैठे लोगों को महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ठोस पहल करने की आवश्यकता है लेकिन जहां जनता महंगाई से त्रस्त है।

वेब मीडिया का सफलतम उपयोग करने को सूचना महानिदेशक को लिखा पत्र

संवाददाता देहरादून। उत्तराखंड भारत के लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों के महासंघ के अध्यक्ष चन्द्रशेखर जोशी ने सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक को पत्र लिखकर राज्य में विभाग द्वारा वेब मीडिया का सफलतम उपयोग करने की मांग की है।

जारी एक बयान में जोशी ने महानिदेशक को लिखे गये पत्र में कहा है कि कोरोना वायरस कोविड 19 के कारण राज्य सरकार ने कावंड़ यात्रा स्थगित की गई है, इसे देखते हुए पुलिस ने बॉर्डर को बाहरी राज्यो से आने वाले श्रद्वालुओं के लिये सील कर दिया है, परन्तु बाहरी राज्यों के श्रद्वालुओ को इसकी जानकारी न होने से उत्तराखंड के बॉर्डर पर कई कई किलोमीटर लम्बी वाहनों की लाइन लग जा रही है, और बॉर्डर से लोगो को वापस भेजने के लिये पुलिस को जमकर पसीना बहाना पड़ रहा है, और तनाव की नौबत आ रही है।

संक्षिप्त समाचार

23.52 करोड़ के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

संवाददाता देहरादून। केदारनाथ धाम में एडमिन कार्यालयों, अस्पताल एवं अन्य कार्यों हेतु रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं केदारनाथ उत्थान चौरिटेबल ट्रस्ट के मध्य रू0 23.52 करोड़ के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नई दिल्ली में इस समझौता ज्ञापन पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से कम्पनी के सी.ई.ओ. श्री एस. एन. श्रीनिवास एवं उत्तराखण्ड सरकार की ओर से अपर स्थानिक आयुक्त श्रीमती इला गिरी ने हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के अनुसार लगभग 27000 वर्गफीट में एडमिन कार्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कार्य के साथ ही मूलभूत सुविधाओं जैसे वाटर सप्लाई नेटवर्क, सीसीटीवी नेटवर्क, पब्लिक एड्रेस सिस्टम कुण्ड आदि के नवीनीकरण का कार्य किया जाएगा।

आप ने रायपुर विस में कई वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति की

संवाददाता देहरादून। आम आदमी पार्टी ने संगठन निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी ने देहरादून की रायपुर विस में कई वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति की है और इसके साथ ही अभी से ही आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव की शुरूआत कर दी है। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पार्टी केन्द्रीय नेतृत्व ने दिल्ली के संगम विहार के विधायक दिनेश मोहनिया को प्रदेश प्रभारी बनाया है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक
प्रदीप चौधरी
द्वारा
एल.के प्रिटर्स,74/9,आराघर,देहरादून से मुद्रित
व जाखन जोहड़ी रोड,
पी.ओ–राजपुर, देहरादून से प्रकाशित।
संपादकः प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालयः
शिवम् मार्केट, द्वितीय तल
दर्शनलाल चौक, देहरादून।
फैक्स नं०–
0135-2650558
(M) 9319700701
pagethreedaily@gmail.com
आर.एन.आई.नं0
UTTHIN\2005\15735
सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून ही मान्य होगा।